

केंद्रीय बजट पुनर्विचार या स्थिरता का लिट्मस टेस्ट है

द हिन्दू

पेपर- III
(भारतीय अर्थव्यवस्था)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले सप्ताह 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है। बजट सिर्फ सरकार के राजस्व और व्यय का ब्यौरा नहीं है। इसे मौजूदा सरकार की नीति और राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट समझा जाना चाहिए।

2019 के विपरीत, जब भाजपा के पास लोकसभा में 303 सीटें थीं, अब उसके पास 240 सीटें हैं। गठबंधन की राजनीति और क्षेत्रीय गठबंधन सहयोगियों की आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाजपा की सीटों की संख्या में कमी 2019-24 में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के प्रति असंतोष और असंतोष का संकेत दे सकती है। इस बार के आम चुनाव को 'सामान्य' कहा गया, जिसका अर्थ है कि चुनाव अभियान का ध्यान 'रोटी और मक्खन' के मुद्दों पर था, जबकि 2014 और 2019 में इसे आकांक्षात्मक और भावनात्मक मुद्दे कहा गया था।

ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने अपनी चिंताओं और बेचौनियों को दूर करने में सरकार की विफलता पर अपनी निराशा को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। इसलिए, इस बजट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं।

रोजगार का मुद्दा चुनावी मुद्दा

2024 के आम चुनाव में अभियान के प्रमुख मुद्दों में से एक बेरोजगारी, मुद्रास्फीति की चिंता और सामाजिक और आर्थिक न्याय से जुड़े सवाल थे। रोजगार, विशेष रूप से, आर्थिक दृष्टिकोण से अन्य प्रश्नों को संबोधित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय भूमिका निभाने के रूप में देखा जा सकता है। तो, इस उद्देश्य को संबोधित करने में बजट क्या कर सकता है? शिकागो स्कूल ऑफ थॉट और कोलंबिया विश्वविद्यालय के लोगों द्वारा दोहराए गए इसके मेजानाइन संस्करण के प्रति निष्ठा रखने वाले अर्थशास्त्रियों ने पहले ही सरकार द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास के विचार का आक्रामक विरोध व्यक्त किया है। निहितार्थ से, यह पहले से ही उपेक्षित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कार्यक्रम के लिए संभावित आवंटन के साथ-साथ शहरी बेरोजगारों के लिए एक समान कार्यक्रम की मांगों को लक्षित करता है।

हमें यह समझना होगा कि मनरेगा निजी क्षेत्र या बाजार के माध्यम से रोजगार पैदा करने के मामले में नवउदारवादी विकास नीति की विफलता का परिणाम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड (सीएमआईई) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा रोजगार पर हाल की रिपोर्टों ने भारत में रोजगार की समस्या के बारे में चिंताओं को उजागर किया है। रिपोर्ट में तीव्रता के अलग-अलग स्तरों (विभिन्न तरीकों के कारण) के साथ, अल्परोजगार के बहुत ऊंचे स्तर; युवाओं (15-29 वर्ष) में बेरोजगारी; और विशेष रूप से शिक्षित युवाओं (माध्यमिक स्कूल शिक्षा से ऊपर) के बीच बेरोजगारी की ओर इशारा किया गया है। इसके अलावा, नियमित रूप से कार्यरत लोगों की वास्तविक आय में संकुचन देखा गया है, शायद अनौपचारिकता के उच्च स्तर और खराब गुणवत्ता वाले रोजगार के कारण। दूसरी ओर, जबकि आकस्मिक श्रम की आय में वृद्धि हुई है।

श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन यह अवैतनिक पारिवारिक श्रम और घरेलू आय के पूरक के रूप में अधिक है। रोजगार के मामले में संरचनात्मक प्रतिगमन के साथ-साथ इन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, जिसका अर्थ है कि रूढ़िवादी कल्पना के विपरीत, प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि हुई है और द्वितीयक क्षेत्र के रोजगार में संकुचन हुआ है। यह असंगठित क्षेत्र, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के महत्वपूर्ण संकुचन के कारण है।

एमएसएमई क्षेत्र में संकुचन

कम से कम तीन झटकों - नोटबंदी, माल और सेवा कर (जीएसटी) और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण एमएसएमई क्षेत्र में काफी गिरावट आई है। इस बजट में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र को सूक्ष्म समझ की आवश्यकता है। पहले के बजटों में बुनियादी ढांचे (कैपेक्स), कौशल-आधारित कार्यक्रमों, स्टार्ट-अप के लिए ऋण और रोजगार पैदा करने के लिए राजकोषीय विवेक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें से अधिकांश हस्तक्षेपों में आपूर्ति पक्ष की नीति पूर्वाग्रह के साथ-साथ उच्च मूल्य वाली अंतिम गतिविधियों की सेवा भी रही है। एमएसएमई सेगमेंट में भी, सरकार का जोर उन एमएसएमई पर रहा है जो निर्यात उन्मुख हैं, यह देखते हुए कि उच्च मूल्य वाले उत्पादन और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के साथ-साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और निर्यात उन्मुख क्षेत्रों वाले उद्यमों में उच्च मूल्य वर्धित लेकिन बहुत कम रोजगार लोच है। इसलिए, फोकस को विकास के लिए विकास को प्राथमिकता देने से बदलकर रोजगार पैदा करने और समावेशी विकास की ओर बदलना होगा।

ध्यान कहाँ होना चाहिए

सामाजिक और आर्थिक न्याय को खोखला नहीं माना जाना चाहिए। इस बजट में एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो निम्न आय वर्ग के घरेलू उपभोग को पूरा करते हैं, जो सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूह भी हैं। इसके अलावा, मानव विकास सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमडीपीआई) पर भारत के खराब प्रदर्शन को देखते हुए, वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को इस बजट में रोजगार सृजन उद्देश्यों के साथ अधिक आवंटन मिलना चाहिए। हाल के दिनों में, भारत के पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर बढ़ने की बयानबाजी, बेरोजगारी और खराब गुणवत्ता वाले रोजगार विकास की समस्या के साथ-साथ मौजूद रही है - जो 1990 के दशक के मध्य से ही देखी जा रही है। जबकि राजनीतिक चालें पुनर्विचार के लिए कोई मूड नहीं दिखाती हैं, शायद निरंतरता के दृष्टिकोण को पेश करना चाहती हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह का गलत आत्मविश्वास बजट में भी नहीं दिखाई देगा।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : केन्द्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. केन्द्रीय बजट 2024-25, 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।
 2. निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी बजट।
- उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of Union Budget 2024-25-

1. Union Budget 2024-25 will be presented on 23 July.
2. Nirmala Sitharaman will present the budget for the 7th consecutive time.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 & 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : (c)

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Mains Expected Question & Format)

प्रश्न: हालिया लोकसभा चुनावों के परिणामों के मद्देनजर आगामी केन्द्रीय बजट में क्या नवीन प्रवृत्तियां एवं पिछले वर्षों की तुलना में क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं? चर्चा करें।

उत्तर का एप्रोच :

- उत्तर के पहले भाग में लोकसभा चुनावों के परिणामों से निर्मित नई परिस्थितियों की चर्चा की जाए।
- दूसरे भाग में आगामी केन्द्रीय बजट में क्या नवीन प्रवृत्तियां एवं पिछले वर्षों की तुलना में क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं उनकी चर्चा करनी है।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।